एस. पी. बाँगढ़ न्यायमूर्ति के समक्ष

मनोज, पुत्र हंसराज —*अपीलार्थी*

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी

2009 का सीआरए नंबर एस -765-एसबी

सितम्बर 26, 2012

भारतीय दंड संहिता- Ss.363, 366-A, 3 76 & 120-B - साथियों की मदद से दोषसिद्धी-अपीलकर्ता के खिलाफ अपील, अभियोक्ता के साथ भाग गया और उसके साथ संभोग किया - संभोग सहमति से साबित हुआ - स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम थी - तर्क दिया कि अभियोक्ता की सही उम्र का पता लगाने के लिए अस्थिभंग परीक्षण की आवश्यकता थी - आयोजित, साक्ष्य का दायित्व अपीलकर्ताओं पर यह साबित करने के लिए है कि वह घटना के समय 16 वर्ष से अधिक आयु की थी - स्कूल प्रमाण पत्र केवल तभी निरस्त किया जाएगा जब अपीलकर्ताओं द्वारा कुछ विपरीत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है - अपीलकर्ता एक युवा व्यक्ति है जिसे पहले दोषी नहीं ठहराया गया है - उसकी सजा को घटाकर पांच साल कर दिया गया है - अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता द्वारा ली गई दलील को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी के खिलाफ उसकी उम्र निर्धारित करने के लिए अभियोक्ता पर अस्थिभंग परीक्षण के गैर-प्रदर्शन के कारण प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यह केवल तभी प्रासंगिक होता, जब अपीलकर्ता ने अभियोक्ता के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने की दलील नहीं ली होती।

(पैरा 23)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि यहां तक कि, पीडब्लू -2 डॉ अर्चना यादव को प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई सुझाव नहीं दिया गया था कि घटना के समय अभियोक्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक थी या उसकी जन्म तिथि 05.12.1992 नहीं थी। पीडब्लू-2 डॉ. अर्चना यादव के सामने इस प्रकार के प्रश्न न पूछकर अपीलकर्ता पीडब्लू-2 डॉ. अर्चना यादव के समक्ष अभियोक्ता द्वारा बताई गई उम्र से संतुष्ट रही।

(पैरा 24)

आगे कहा गया, कि प्रमाण पत्र Ex.PE केवल तभी रद्द किया जा सकता है, यदि, कुछ विपरीत प्रमाण पत्र, अपीलकर्ता द्वारा अभियोक्ता के आयु प्रमाण के संबंध में प्रस्तुत किया गया होगा।

(पैरा 25)

आगे कहा गया, कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार, सही निष्कर्ष निकाला कि घटना के समय अभियोक्ता की उम्र 16 वर्ष से कम थी और इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ सहमति से यौन संबंध धारा 376आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के कमीशन को आकर्षित करता है। अपीलकर्ता ने अभियोक्ता को वैध संरक्षकता से अपहरण कर लिया और उसे उसके साथ अवैध संभोग के लिए प्रलोभन के लिए प्रेरित किया।

(पैरा 26)

आगे कहा गया कि इस प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 363 और 366-ए आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जिसे दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय के माध्यम से दोषी ठहराया गया, जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए और पुष्टि की जानी चाहिए।

(पैरा 27)

अपीलकर्ता के लिए ***अधिवक्ता अरुण यादव।***

जीएस संधू, एएजी, हरियाणा ***प्रतिवादी के लिए।***

एस.आर. बांगढ़ , न्यायमूर्ति

1. अपील में सत्र मामला में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, रेवाड़ी द्वारा पारित दिनांक 27-02-2009 के दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की वैधता और औचित्य को चुनौती दी गई है। 2008/2007 की आरटी/35, एफआईआर नंबर 157 दिनांक 12.07.2007 से उत्पन्न, पुलिस स्टेशन खोल में दर्ज भारतीय दंड संहिता (संक्षिप्त आईपीसी के लिए) की धारा 363,366-ए, 376 और 120-बी के तहत, जिसके तहत, अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और 500 रुपये का जुर्माना देने या जुर्माना अदा करने में चूक करने पर एक महीने के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। आईपीसी की धारा 363; आईपीसी की धारा 366-क के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 500/- रुपए का जुर्माना अथवा जुर्माना अदा न करने पर एक माह के कठोर कारावास की सजा भुगतने और सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतने तथा 500/- रुपए का जुर्माना अदा करने अथवा जुर्माना अदा न करने पर दंडनीय अपराध करने के लिए एक माह के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी आईपीसी की धारा 376 के तहत। सभी मूल सजाओं को समवर्ती रूप से चलाने का आदेश दिया गया था और तत्काल मामले की जांच/पूछताछ/विचारण के दौरान अपीलकर्ता द्वारा पहले से ही हिरासत की अवधि को मूल वाक्यों से अलग करने का आदेश दिया गया था।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 10.07.2007 को लगभग 5.00 बजे, अपीलकर्ता ने सतनारायण (शिकायतकर्ता) के पिता के घर में बुरे इरादे से प्रवेश किया और जब वह मवेशियों को चारा उपलब्ध कराने के बाद घर पहुंचा, तो वह (अपीलकर्ता) घर की छत से कूदकर उनके घर से भाग गया। उनके गांव की दो महिलाएं, जो जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए वहां आई थीं, उन्होंने कूदने का शोर सुना। 'हायइस मामले की सूचना ग्राम पंचायत को दी गई, साथ ही अपीलकर्ता के चाचाओं को भी, अपीलकर्ता

निर्मला (अपीलकर्ता की मां) के साथी ने कहा कि अब उसका बेटा केवल उनके घर में प्रवेश कर गया है और भविष्य में, वह उनकी बेटी के साथ भाग जाएगा। अगले दिन अर्थात 11.07.2007 को, अभियोक्ता जिसकी जन्मतिथि 05.12.1992 थी और वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जैनाबाद में 10 वीं कक्षा में पढ़ रही थी, स्कूल ड्रेस में स्कूल गई थी, उसके बाद, सुभाष की बेटी सरिता, जो अपीलकर्ता की चचेरी बहन है, एक पूर्व-नियोजित योजना के तहत अभियोक्ता को उसके घर ले गई। अपीलकर्ता और सुभाष की पत्नी कृष्णा पहले से ही वहां मौजूद थे और उसके बाद, अपीलकर्ता एक पूर्व नियोजित योजना के तहत उसे प्रलोभन देकर एक अज्ञात स्थान पर ले गया। उसकी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिली।

3. सतनारायण (शिकायतकर्ता) ने दिनांक 12-07-2007 को अपराह्न लगभग 12.50 बजे बस स्टैंड, दाहिना में हरपाल सिंह एएसआई के नेतृत्व में पुलिस पार्टी से मुलाकात की और उपर्युक्त आरोपों वाला एक आवेदन प्रदर्श पीडी प्रस्तुत किया, जिस पर हरपाल सिंह एएसआई ने पृष्ठांकन प्रदर्श पीडी/3 किया और उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया, जहां औपचारिक एफआईआर प्रदर्श पीडी/1 दर्ज किया गया था। उन्होंने प्रदर्श पीके को प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, जैनाबाद में एक आवेदन दिया और बाद में अभियोक्ता प्रदर्श पीके/हरपाल सिंह की जन्म तिथि के बारे में पृष्ठांकन किया और अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मौके का दौरा किया और रफ साइट प्लान प्रदर्श पीएल तैयार किया। उन्होंने सिविल अस्पताल से अपीलार्थी मेडिको की कानूनी जांच भी कराई। 13.07.2007 को अपीलकर्ता की चिकित्सा जांच के बाद, उसने अपने (अपीलकर्ता) अंडरवियर का पार्सल बनाया, जिसे मेमो प्रदर्श पीएन के तहत जब्त कर लिया गया और उस पार्सल को रासायनिक परीक्षक, मधुबन को भेज दिया गया। उसी दिन, उन्होंने अभियोक्ता की चिकित्सा जांच के बाद पार्सल प्राप्त किया था और ज्ञापन प्रदर्श पीजी के माध्यम से उस पार्सल को जब्त कर लिया था।

4. जांच पूरी होने के बाद, पुलिस स्टेशन खोल के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने विद्वान इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट दर्ज की, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने धारा 363, 366-ए और 376 आई पीसी के तहत दंडनीय अपराध किए हैं। पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, धारा 207 सीआरपीसी के तहत आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां अपीलकर्ता को प्रस्तुत की गईं और मामला बाद में सत्र न्यायालय में विचारण के लिए सौंप दिया गया, जहां अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 363, 366-ए और 376 आईपीसी के तहत आरोप तय किए गए, जिसके लिए, बाद वाले ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया। नतीजतन, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य तलब किए गए। 19.03.2008 को, अभियोक्ता की विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष पी डब्ल्यू -1 के रूप में जांच की गई थी और उसकी परीक्षा के बाद, सरिता और निर्मला को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और तदनुसार, दोनों को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 28.03.2008 के आदेश के तहत और उनकी उपस्थिति के बाद तलब करने का आदेश दिया गया था। सरिता और निर्मला के खिलाफ धारा 363, 366-ए, 376 के साथ 120-बी आई पीसी के तहत आरोप तय किए गए थे, जहां उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे

का सामना करने का दावा किया।

7. मुकदमे के लंबित रहने के दौरान सरिता आरोपी को विचारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड के पास भेजा गया था।

8. मुकदमे में, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू -1 के रूप में अभियोक्ता की जांच की, डॉ अर्चना यादव को पीडब्ल्यू-2 के रूप में, डॉ विजय पाल को पीडब्लू -3 के रूप में, सतनारायण शिकायतकर्ता को पीडब्ल्यू -4 के रूप में, संत्रा को पीडब्ल्यू -5 के रूप में, कंवर सिंह को पीडब्लू -6 के रूप में, श्रीकृष्ण इंस्पेक्टर को पीडब्ल्यू -7 के रूप में, धर्म पाल को पीडब्लू -8 के रूप में, भागीरथ एचसी को पीडब्लू -9 के रूप में, धन राज को पीडब्लू -10 के रूप में, देश राज को पीडब्लू -11 के रूप में, सुखराम पाल को पीडब्लू -12 के रूप में, रवि कुमार कांस्टेबल को पीडब्लू -13 के रूप में जांचा गया, हरपाल सिंह एएसआई पीडब्लू-14, उदय भान एएसआई पीडब्ल्यू-15 के रूप में और बाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद साक्ष्य बंद कर दिया एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पीएक्स।

9. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बंद होने के बाद, अपीलकर्ता और उसके साथी से धारा 313 सीआरपीसी के तहत पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के आरोपों से इनकार किया, इस मामले में निर्दोष और झूठे आरोप लगाए। उन्होंने डॉ. विजय रुस्तोगी, हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की डीडब्ल्यू-1 के रूप में भी जांच की और बाद में बचाव साक्ष्य को बंद कर दिया।

10. दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि इस फैसले के पहले पैराग्राफ में वर्णित है, जबकि अपीलकर्ता के सहयोगी निर्मला को बरी कर दिया। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता, जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त था, इस अपील में उसकी स्वीकृति और उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप को बरी करने की प्रार्थना के साथ आया है।

11. अपीलकर्ता के विद्वान वकील और प्रतिवादी के लिए सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा को सुना गया है और उनकी सहायता से विद्वान ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया है।

12. सबसे पहले, यह देखा जाना चाहिए कि इस मामले में पीडब्लू ने क्या गवाही दी।

13. अभियोक्ता पीडब्लू -1 के रूप में उपस्थित हुई और गवाही दी कि 11.07.2007 को, वह अपने स्कूल गई, जहां अपीलकर्ता की सरिता बहन ने उससे अपने घर चलने का अनुरोध किया और तदनुसार, वह उसके साथ अपने घर गई, जहां उसने अपीलकर्ता की नीमो मां और कृष्णा को मामा और बाद में खुद को पाया। उसने आगे गवाही दी कि नीमो (अपीलकर्ता की मां) ने अपीलकर्ता को उसे एक कमरे में ले जाने के लिए कहा और तदनुसार, उसे अपीलकर्ता द्वारा अपने कमरे में ले जाया गया और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया और वह रोई जब उसके साथ बलात्कार किया जा रहा था और अपीलकर्ता ने उसे जान से मारने की धमकी दी, साथ ही, उसके भाई और बहन भी। उसने आगे गवाही दी कि नीमो (अपीलकर्ता की मां) ने अपीलकर्ता को पैसे दिए और उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया और फिर अपीलकर्ता उसे ट्रैक्टर पर सीहा ले गया और उसी दिन, वह उसे एक बस में रेवाड़ी

ले गया और वहां से किसी अन्य स्थान पर और उसे एक दिन के लिए अपने चाचा के घर पर रखा, जहां भी, अपीलकर्ता ने रात के समय उसके साथ बलात्कार किया और 13.07.2007 को, वह उसे गांव सीहा ले आया और उसके पिता और पुलिस उसकी तलाश में वहां आए और उसके पिता ने उसे देखा और वह अपने पिता के पास आई जो उसे वापस ले आए। उसने आगे गवाही दी कि 10.07.2007 को लगभग 5.00 बजे, उसके चाचा शेर सिंह अपीलकर्ता के घर गए और उसकी मां से अनुरोध किया कि वह अपीलकर्ता को इस तरह के आचरण से रोके और अपीलकर्ता की मां ने अपीलकर्ता को रोकने के बजाय कहा कि आज वह (अपीलकर्ता) घर में प्रवेश कर चुका है और अब वह उसे ले जाएगा। उसने आगे गवाही दी कि उसकी कानूनी जांच की गई थी और पुलिस ने उसका बयान एक्ज़िबिट पीए दर्ज किया था जिसमें उसके हस्ताक्षर हैं।

14. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि बाद में, अभियोक्ता के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे, जो अपराध के कथित कमीशन के समय 16 वर्ष से अधिक आयु का था और इसलिए, अपीलकर्ता बरी होने का हकदार है और विद्वान ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से दोषी ठहराया और उसे धारा 363 के तहत दंडनीय अपराधों के कथित कमीशन के लिए सजा सुनाई, 366-ए और 376 आईपीसी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोक्ता की जन्मतिथि निर्धारित करने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र प्रदर्शनी पीई पर गलत तरीके से भरोसा किया गया था, जिसे 05.12.1992 के रूप में लिखा गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोक्ता की आयु निर्धारण के लिए उसका अस्थिकरण परीक्षण किया जाना आवश्यक था, जिसे आयोजित नहीं किया गया है और अभियोक्ता पर अस्थिभंग परीक्षण न करने के कारण उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना आवश्यक था और उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक रखने के लिए, विद्वान ट्रायल कोर्ट को अपीलकर्ता को बरी कर देना चाहिए था।

15. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने माखन [1] ***बनाम मध्य प्रदेश*** राज्य, गुरदीप ***सिंह बनाम हरियाणा राज्य, अरविंदर कौर*** [2] ***बनाम पंजाब राज्य, मोहम्मद जमतेज खान*** बनाम हरियाणा राज्य भूप ***सिंह बनाम हरियाणा राज्य, जयपाल सिंह*** [3] ***बनाम*** [4] [5] ***हरियाणा*** राज्य[6], ***सोमनाथ*** पर भी भरोसा किया(***ग) इस न्यायालय और अन्य माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित बनाम पंजाब राज्य , राकेश*** [7] ***बनाम***

[1] 2003 (3) आरसीआर (आपराधिक) 674

[2] 1996 (3) आरसीआर (आपराधिक) 640

[3] 2007 (3) आरसीआर (आपराधिक) 818

[4] 1994 (2) आरसीआर 456

[5]2005 (3) आरसीआर (आपराधिक) 63

[6] 2003 (2) आरसीआर (आपराधिक) 310

[7] 2008 (3) आरसीआर (आपराधिक) 510

हरियाणा राज्य और ***राम प्रताप@ मकिया[8] बनाम राजस्थान राज्य के[9] मामले में उच्चतम न्यायालय के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10-11-2010 को पारित*** किया था। ये निर्णय उन मामलों में दिए गए थे, जहां अभियोक्ता की आयु 16 वर्ष से अधिक थी और कुछ निर्णयों में, अभियुक्त द्वारा यह दलील नहीं दी गई थी कि उसने अभियोक्ता के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे। इसलिए, ये निर्णय अपीलकर्ता के लिए अप्रासंगिक हैं और इससे उसके द्वारा कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

16. यह अपीलकर्ता का स्वीकृत मामला है कि उसका उस अभियोक्ता के साथ प्रेम संबंध था जिसने उसे कई पत्र लिखे थे। यह अपीलकर्ता का भी मामला है कि अभियोक्ता उसके (अपीलकर्ता) के पीछे पड़ी हुई थी और घटना के समय, वह 18 वर्ष से अधिक आयु की थी।

17. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना कि हालांकि अभियोक्ता एक सहमति पक्ष साबित हुआ है, फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह 16 वर्ष से कम उम्र की थी, अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 363, 366-ए और 376 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के कमीशन के लिए आरोप किसी भी उचित संदेह से परे साबित हुए हैं और वह था, तदनुसार, इसके तहत दोषी ठहराया गया।

18. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष पर आपत्ति नहीं जताई है, जिसने यह भी तर्क दिया था कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे और वह 18 वर्ष से अधिक उम्र की थी।

19. अब, जब एक बार अपीलकर्ता द्वारा यह दलील दी गई कि उसने अभियोक्ता के साथ सहमति से यौन संबंध बनाए थे, तो यह दिखाने की जिम्मेदारी उस पर आ गई कि प्रासंगिक रूप से, अभियोक्ता ने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। प्रारंभ में, अपीलकर्ता ने अभियोक्ता के साथ छेड़खानी की और इस इश्कबाज के बाद सहमति से यौन संबंध बनाए गए। इश्कबाज़ी के समय, साथ ही, अभियोक्ता के साथ सहमति से यौन संबंध रखने के समय, यह सत्यापित करना उसका बाध्य कर्तव्य था कि अभियोक्ता 16 वर्ष से अधिक आयु की थी ।

20. अपीलकर्ता ने निस्संदेह यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं रखा है कि उसके द्वारा अभियोक्ता के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने के समय, वह उस दस्तावेज के अनुसार 16 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी थी। प्रतिवादी ने स्कूल प्रमाण पत्र पर भरोसा किया प्रदर्श पीई एकॉर्डिंग, उस प्रमाण पत्र के अनुसार, अभियोक्ता का जन्म 05.12.1992 को हुआ था और घटना की तारीख यानी 11.07.2007 को, वह 16 वर्ष से कम आयु की थी। कोई भी यह समझने में विफल रहता है कि अभियोक्ता की उम्र के प्रमाण के बारे में इस प्रमाण पत्र को कैसे निरस्त किया जा सकता है। यदि, यह स्कूल प्रमाण पत्र प्रदर्श पीई जिसमें उसकी जन्मतिथि 05.12.1992 है, उसका नहीं है, तो यह किसका है। मुकदमे के दौरान अपीलकर्ता द्वारा

[8] 2006 (4) आरसीआर (आपराधिक) 505

[9] 2007 (4) आरसीआर (आपराधिक) 108

इस सबूत का नेतृत्व किया जाना आवश्यक था कि यह प्रमाण पत्र प्रदर्श पीई जिसमें अभियोक्ता की जन्म तिथि 05.12.1992 है, किसी अन्य लड़की से संबंधित है।

21. इसलिए, संक्षेप में, यह अपीलकर्ता को यह दिखाना था कि अभियोक्ता 11.07.2007 को 16 वर्ष से अधिक आयु की थी ।

22. पीडब्लू-2 डॉ. अर्चना यादव, चिकित्सा अधिकारी, सरकारी अस्पताल, रेवाड़ी ने 13.07.2007 को पीड़िता की चिकित्सा विधि जांच की और उससे पहले, अभियोक्ता ने उसकी उम्र 15 वर्ष बताई थी। जैसा कि पहले ही माना जा चुका है, अभियोक्ता की प्रति प्रदर्श पीई के मध्य मानक प्रमाण पत्र में, जिसे पीडब्लू-6 कंवर सिंह, प्रभारी/प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जैनाबाद द्वारा सिद्ध किया गया है, अभियोक्ता की जन्म तिथि 05.12.1992 लिखी गई है। विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके द्वारा दिए गए सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिनांक 14.07.2007 के अपने बयान में, उसने खुद को 15 साल की उम्र बताया था।

23. अपीलकर्ता द्वारा ली गई दलील को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी के खिलाफ उसकी उम्र निर्धारित करने के लिए अभियोक्ता पर अस्थिभंग परीक्षण के गैर-प्रदर्शन के कारण प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यह केवल तभी प्रासंगिक होता, जब अपीलकर्ता ने अभियोक्ता के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने की दलील नहीं ली होती।

24. यहां तक कि, पीडब्लू -2 डॉ अर्चना यादव को क्रॉस-परीक्षा के दौरान कोई सुझाव नहीं दिया गया था कि घटना के समय अभियोक्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक थी या उसकी जन्म तिथि 05.12.1992 नहीं थी। पीडब्लू-2 डॉ. अर्चना यादव के सामने इस प्रकार के प्रश्न न पूछकर अपीलकर्ता पीडब्लू-2 डॉ. अर्चना यादव के समक्ष अभियोक्ता द्वारा बताई गई उम्र से संतुष्ट रही।

25. प्रमाण पत्र पूर्व पीई को केवल तभी निरस्त किया जा सकता है, यदि अपीलकर्ता द्वारा अभियोक्ता के आयु प्रमाण के संबंध में कोई विपरीत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया होता।

26. इस प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला कि घटना के समय अभियोक्ता की उम्र 16 वर्ष से कम थी और इसलिए, अपीलकर्ता के साथ सहमति से यौन संबंध आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के कमीशन को आकर्षित करता है। अपीलकर्ता ने अभियोक्ता को वैध संरक्षकता से अपहरण कर लिया और उसे उसके साथ अवैध संभोग के लिए प्रलोभन के लिए प्रेरित किया।

27. इस प्रकार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 363 और 366-ए आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया, दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए और पुष्टि की जानी चाहिए।

28. इस स्थिति का सामना करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उत्तरार्द्ध, पिछले दोषी नहीं है, जो पहले से ही पर्याप्त समय के लिए हिरासत में है; वह पहले से ही आईएस मुकदमेबाजी की पीड़ा का सामना कर चुका है और इससे महिला लोक के प्रति उसके व्यवहार में जबरदस्त परिवर्तन आया होगा और इन विशेष कारणों से, अदालत को सही तरीके से देखते हुए, आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय

अपराध करने के लिए उसकी सजा को 7 साल से कम किया जा सकता है।

29. अपीलकर्ता पहले से दोषी नहीं है। वह एक ऐसा युवक है जो पहले ही इस मुकदमे की पीड़ा से गुजर चुका है। वह भी लंबे समय से जेल में है। ***गुरमीत सिंह और अन्य*** बनाम ***हरियाणा राज्य के***[10] मामले में इस अदालत ने कहा कि यदि अपीलकर्ता की सजा आईपीसी की धारा 376 के तहत चार साल तक कम कर दी जाती है तो न्याय का लक्ष्य पर्याप्त होगा। इस फैसले में, यह माना गया था कि लड़की की उम्र 15 1/2 वर्ष थी, जो काफी परिपक्व थी, हालांकि वह 16 वर्ष से कम थी। शायद वो गुरमीत सिंह के साथ सेक्स एन्जॉय करना चाहती थी और इसी वजह से वो अपने घर से बाहर आ गई थी.

30. इस फैसले का लाभ अपीलकर्ता मनोज को दिया जाना चाहिए और तदनुसार, आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए उसकी सजा को घटाकर पांच साल कर दिया जाना चाहिए।

31. परिणामस्वरूप, सजा के क्रम में पूर्वोक्त संशोधन को छोड़कर, अपील विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी

.

[10] 1999 (2) एआईसीएलआर 472